

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

क्या मोदी सरकार रोजगार देती नहीं है, बेच देती है ?

हूबहू व्यापम की तर्ज पर हो रहा SSC भर्ती परीक्षा में घोटाला
कर्मचारी चयन आयोग आंदोलन रत छात्रों की सभी माँगें स्वीकार कर भर्ती घोटाले की CBI जाँच
कराए

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार नैतिकता की सारी मर्यादाएं भ्रष्टाचार की खूँटी पर टाँग कर कुम्भकर्णीय नींद में सो गई है। बीते कई दिनों से देश के कोने कोने से आए छात्र भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की चयन परीक्षा में हुए भीषणतम भ्रष्टाचार को ले कर दिल्ली की सड़कों पर हैं। ज्ञातव्य है कि कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कर्मचारी चयन परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर-ग्रेड D और C, सेंट्रल एक्साइज़ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर-इन्कम टैक्स, असिस्टेंट इंफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीबीआई, ऑडिटर्स और एकाउंटेंट्स सीएजी इत्यादि के अलावा ग्रुप D से LDC ग्रेड के प्रमोशन और LDC से UDC ग्रेड के प्रमोशन के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करता है।

15 - 16 परीक्षाएं विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रति वर्ष कराई जाती हैं। लगभग 12 हजार से 40 हजार सीटों के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राएं इन भर्ती परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाते हैं। इन प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए छात्र जी तोड़ मेहनत करते हैं।

भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे नौजवानों का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो देश के नौकरी की अपेक्षा रखने वाले नौजवानों के भविष्य को बेचने का काम कर रहा है। नियोजित रूप से प्रश्न पत्रों को लीक किया जाता है, और छात्रों के भविष्य की कीमत 40 लाख से लेकर 50 लाख रु तक तय की जा रही है।

अब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि इस वर्ष की चयन परीक्षा CGL टियर -2 के पहले ही दिन, 17 फरवरी को SSC को एक केंद्र पर दूसरी शिफ्ट की यह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी, और फिर पुनः निर्धारित की गई तो यह बात सामने आई कि यह पेपर भी लीक हो चुके हैं। और छात्रों द्वारा सप्रमाण इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई इन्क्वायरी की मांग की गई। मगर चयन आयोग के चेयरमैन ने इस गंभीर भ्रष्टाचार का समग्र रूप से संज्ञान लेने की अपेक्षा सिर्फ 21 फरवरी की उसी शिफ्ट की परीक्षा पुनः आयोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि सभी शिफ्ट परीक्षाएं उतनी ही संदेहास्पद हैं, और समूची परीक्षा पुनः आयोजित की जानी चाहिए थी। यह पहला अवसर नहीं है जब SSC भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की शिकायत आई हो। इसके पहले भी 30 नवंबर 2016 को SSC -CGL टियर -2 परीक्षा में 14 केंद्रों पर सामूहिक नकल के प्रकरण सामने आए थे। इसी तरह 16 अगस्त 2017 को जयपुर में पर्यवेक्षकों द्वारा ऑन लाइन परीक्षा में स्क्रीन-शॉट लेकर पेपर सॉल्व कराने की FIR भी कराई गई थी। और उसी दौरान इलाहाबाद में भी बोगस कैंडिडेट परीक्षा देते पाए गए थे।

SSC भर्ती परीक्षा में कदाचरण को लोकसभा में 30 -11 -2016 को प्रश्न क्रमांक 2301 के जवाब में स्वीकारा गया है। अर्थात् सामूहिक नकल, प्रश्न पत्र का लीक होना, बोगस छात्रों का किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना, ये सारा तरीका हूबहू मप्र में हुए व्यापम घोटाले जैसा है, जो वहाँ 2006 से, जबसे भाजपा सरकार आई है, तब ही से किया जा रहा था। तो क्या इसका आशय यह है कि भाजपा सरकारें करोड़ों युवाओं के भविष्य को बेचने का नियोजित षडयंत्र कर रही हैं? पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद सरकार का व्यापक स्तर पर कार्यवाही नहीं करना तो यही दर्शाता है।

छात्र चाहते हैं इस व्यापम से भी बड़े घोटाले की CBI जाँच कराई जानी चाहिए। जबकि SSC की मंशा सिर्फ SIT जाँच, वह भी अपने अधीनस्थ कर्मियों से कराए जाने की है। SSC की इस मंशा से साफ़ है कि वह इस भर्ती परीक्षा के भ्रष्टाचार पर न सिर्फ़ पर्दा डालना चाहती है, अपितु इसे जारी भी रखना चाहती है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माँग की है कि तुरन्त आंदोलनरत छात्रों की सभी माँगों को केंद्र की भाजपा सरकार स्वीकार करे।